पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में
2024 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.381
वर्ष- 2018 का थाना वाद सं.- 31, थाना- एन.आई.ए., जिला- पटना से उद्भूत,

==========

शिवेन्द्र रजक उर्फ शिलेन्द्र रजक उर्फ शैलेन्द्र रजक, पुत्र- पुरूषोत्तम लाल रजक, ग्राम/मोहल्ला- हाउस नं.- एल- 3/1 पंचशील नगर, नर्मदा रोड, थाना- गोरखपुर, जिला- जबलपुर, मध्य प्रदेश।

..... अपीलार्थी

बनाम

1. बिहार राज्य
2. महानिर्देशक, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली के माध्यम से भारत का संघ।

.... उत्तरदातागण

==========

उपस्थिति :

अपीलार्थी के लिए	:	श्री ठाकुर मनीष मोहन, अधिवक्ता
		श्री अमित पांडे, अधिवक्ता
एन.आई.ए के प्रतिवादी के लिए	:	डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी.,
		श्री मनोज कुमार सिंह, विशेष पीपी एनआईए
		श्री अंकित कुमार सिंह, अधिवक्ता,
		श्री प्रमोद कुमार, पी.पी. एनआईए
		श्री शिवादित्य धारी सिन्हा,एएसजी के एसी

==========

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 - धाराएँ 121, 379, 414, 120 बी साथमें पढ़ा जाए धारा 34 - आयुध आधिनियम, 1959 - धाराएँ 25(1-ए), 25(1 एए), 25(1 बी) (ए)

और धाराएँ 26,35 साथ में पढ़ा जाए धारा 39 विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 - धारा 21(4) - नियमित जमानत - देखने से प्रथमदृष्टया सत्य प्रतित होता है युक्तियुकत आधार पर कि जो भी अभियोग अपीलार्थी पर लगाए गए है, करने योग्य है - विचारण में देरी का कारण दूसरे अभियुक्तों द्वारा एक के बाद एक उन्मोचण आवेदन दाखिल किया जाना है - विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की उपबंध 43 डी (5) लग सकता - विचारण की प्रक्रिया शुरू हो चुकि है और अभी तक लगभग 52 साक्षी अभियोजन द्वारा परीक्षण किया जा चुका है - विशेष न्यायालय ने कोई भी गलती नहीं की है नियमित जमानत अगृहीत/खारिज करने में - अपील खारिज ***(पारा 6.4, 6.6 - 6.8 और 7)***

(2019) 5 एस सी सी 1 - ***निर्भर किया गया***

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री रूद्र प्रकाश मिश्रा

मौखिक निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तिथिः 12-09-2024

अपीलार्थी ने 2018 के आर. सी. मामला संख्या 31 से उत्पन्न 2018 के विशेष मामले संख्या 08 के संबंध में विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन.आई.ए., पटना द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दिनांक 19.02.2024 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम की धारा 21(4) (इसके बाद 'एन.आई.ए. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत वर्तमान अपील दायर की है, जिसके तहत संबंधित विशेष न्यायालय ने जमानत देने के लिए अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया है।

2. वर्तमान अपील दायर करने के लिए संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः -

2.1. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि एक निरीक्षक बिंदेश्वरी यादव ने *अन्य बातों के साथ-साथ* एक लिखित रिपोर्ट दिनांक 05.10.2018 को दर्ज की है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार को भारतीय दंड संहिता (भा. दं. सं.) की धारा 121, 379, 414, 120 बी के साथ पठित धारा 34, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1 ए), 25 (1 एए), 25 (1 बी) (ए) के तहत बिहार के मुंगेर जिले के मुफस्सिल पुलिस स्टेशन में 2018 की एफ. आई. आर. संख्या 323 के पंजीकरण के बारे में जानकारी मिली है। साथ ही तीन ए. के.-47 हथियारों की बरामदगी और सेना शस्त्रागार, जबलपुर (एम. पी.) से विभिन्न राज्यों में माओवादियों और अन्य अपराधियों को ए. के.-47 हथियारों की आपूर्ति में शामिल दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (इसके बाद 'यू.ए.पी.ए.' के रूप में संदर्भित) की धारा 39 के साथ पठित शस्त्र अधिनियम की धारा 26 और 35 के तहत तदनुसार, मामला आर. सी./एन. आई. ए./डी. एल. आई. दिनांक 05.10.2018 के रूप में दर्ज किया गया है।

2.2. एफ.आई.आर. के प्रारूप से यह स्पष्ट है कि कुल मिलाकर 26 व्यक्तियों को अभियुक्तों की श्रेणी में नामित किया गया था। अपीलार्थी को अभियुक्त नं. X II के रूप में प्राथमिकी में दर्शाया गया है।

2.3. यह अपीलार्थी का मामला है कि वह लगभग पिछले छह वर्षों से हिरासत में है और इसलिए, उन्होंने 2018 के आर. सी. संख्या 31 से उत्पन्न 2018 के विशेष मामले संख्या 08 में नियमित जमानत देने के लिए विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन. आई. ए., पटना के समक्ष आवेदन, तथापि, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने दिनांक 19.02.2024 के विवादित आदेश द्वारा उक्त आवेदन को खारिज कर दिया और इसलिए, अपीलार्थी ने वर्तमान अपील दायर की है।

3. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री ठाकुर मनीष मोहन और प्रत्यर्थी एन. आई. ए. के विद्वान विशेष पी. पी. श्री मनोज कुमार सिंह को सुना।

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील मुख्य रूप से यह प्रस्तुत करेंगे कि यद्यपि अपीलार्थी को प्राथमिकी में अभियुक्त संख्या 12 के रूप में रखा गया है, जांच एजेंसी अपीलार्थी को विचाराधीन घटना से जोड़ने वाला कोई सबूत एकत्र करने में विफल रही है और वास्तव में अभियुक्त पुरुषोत्तम लाल रजक का बेटा है, जिसका इकबालिया बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था और इसलिए, अपीलार्थी को फंसाया गया है। विद्वान वकील ने दिनांकित 05.03.2019 को आरोप-पत्र के कागजातों से बताया कि अपीलार्थी का नाम मूल आरोप-पत्र में नहीं है, हालाँकि, पूरक आरोप-पत्र संख्या 1 के पैराग्राफ 16.56 में, अपीलार्थी का नाम संदर्भित किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 14.05.2019 दिनांकित पूरक आरोप-पत्र के पैराग्राफ संख्या 16.38 से 16.41 में, जांच एजेंसी ने अपीलार्थी के बैंक खातों के विवरण का पता लगाया है और बताया है कि कुछ लेनदेन हैं जो अपीलार्थी के बैंक खातों में हुए हैं और यह आरोप लगाया जाता है कि अपीलार्थी ने इसे अवैध स्रोतों से अर्जित किया है और हथियारों की तस्करी से अपराध का मुकदमा चलाया है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी एक होनहार छात्र था और उसने अपना एमबीए पाठ्यक्रम किया था और वह किराने के व्यवसाय में काम कर रहा था।

4.1. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी के खिलाफ प्रतिवादी एन. आई. ए. द्वारा एकत्र की गई एकमात्र सामग्री यह है कि अपीलार्थी अपने

माता-पिता को कटनी रेलवे स्टेशन, जबलपुर, मध्य प्रदेश छोड़ने गया था। इसके अलावा, प्रतिवादी एन. आई. ए. जबलपुर रेलवे स्टेशन या जमालपुर रेलवे स्टेशन से कोई भौतिक सबूत या सी. सी. टी. वी. फुटेज लाने में विफल रहा है कि अपीलार्थी के पिता द्वारा ट्रॉली बैग को मोहम्मद इमरान आलम एवं मो. शमशेर आलम को सौंप दिया गया था।

4.2. विद्वान वकील, इस स्तर पर, प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी अभियोजन एजेंसी ने 150 से अधिक गवाहों का हवाला दिया है, जिनमें से अभियोजन पक्ष ने आज तक 52 गवाहों से पूछताछ की है और इसलिए, वर्तमान मामले की सुनवाई निकट भविष्य में समाप्त नहीं होगी। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों में से किसी ने भी, जिनसे आज तक पूछताछ की गई है, वर्तमान अपीलार्थी के खिलाफ गवाही नहीं दी है।

4.3. विद्वान वकील ने अंत में प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी पिछले छह वर्षों से हिरासत में है और इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी एन. आई. ए. के विद्वान वकील ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रत्यर्थी की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में किए गए कथनों का उल्लेख किया है। विद्वान वकील ने इस न्यायालय के अवलोकन के लिए केस-डायरी के साथ-साथ आरोप पत्र के कागजात भी प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद, विद्वान वकील ने कहा कि आरोपी पुरुषोत्तम लाल रजक द्वारा ए. के.-47 राइफलों की तस्करी ट्राली बैग में रखकर की जा रही थी और उन्हें अपनी पत्नी चंद्रवती देवी के साथ ट्राली बैग में जबलपुर से जमालपुर ले जाया जा रहा था। उक्त पहलू की पुष्टि कटनी रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से होती है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आरोपी पुरुषोत्तम लाल रजक, पूरे रैकेट का सरगना, सुरेश ठाकुर और अन्य सहित अन्य सह-अभियुक्तों की मदद से सी. ओ. डी., जबलपुर से उक्त हथियार निकालता था और आरोपी मोहम्मद नियाज़ुर रहमान उर्फ गुलू, मोहम्मद शमशेर आलम, मो इमरान आलम और बजरंग शंकर, जो इन हथियारों को आगे बेचते हैं। विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान अपीलार्थी, अभियुक्त नं. 12 एफ. आई. आर. में, जांच के दौरान, यह पाया गया कि वह अवैध निषिद्ध हथियारों, यानी ए. के.-47 की साजिश और आपूर्ति में शामिल था। इसके अलावा, सीओडी, जबलपुर से हथियारों की खरीद, इसकी आपूर्ति और वितरण की साजिश आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् पुरुषोत्तम लाल रजक, मनोज सिंह, सुरेश ठाकुर और बजरंग शंकर की संहिता की धारा 164 के तहत दिए गए बयान से स्थापित हुई है।

संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए गवाहों के बयान से भी यह तथ्य स्थापित हुआ। इसके अलावा, जाँच के दौरान संरक्षित गवाह के बयान से भी इसकी पुष्टि हुई है।

5.1. इस स्तर पर, यह भी बताया गया है कि आरोपी पुरुषोत्तम लाल रजक ने 28-29 अगस्त 2018 की रात को जमालपुर तक अपनी पत्नी चंद्रवती देवी के साथ ट्रॉली बैग में एके-47 राइफलों की आपूर्ति की थी। आरोपी पुरुषोत्तम लाल रजक और वर्तमान अपीलकर्ता, प्रत्येक के पास चंद्रवती देवी के साथ एक ट्रॉली बैग था और उन्हें हथियारों की डिलीवरी के लिए जमालपुर के लिए कुर्ला-भागलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए कटनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर देखा गया था। कटनी रेलवे स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए थे।

5.2. प्रतिवादी के विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करेंगे कि जाँच के दौरान, विभिन्न बैंकों में रखे गए अपीलार्थी के बैंक खाते एकत्र किए गए दस्तावेजों और बैंक खातों के विवरणों से पता चलता है कि संबंधित अवधि के दौरान उच्च मूल्य का लेनदेन हुआ था। वास्तव में, अपीलार्थी के पास इस अवैध हथियारों की तस्करी के व्यवसाय के अलावा आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। अपीलार्थी ने उपरोक्त राशि से अपने नाम पर भूमि, दुकान, फ्लैट, वाहन भी खरीदे। इस प्रकार, जांच एजेंसी ने अपीलार्थी के साथ-साथ अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भा. दं. सं. के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और यू.ए.पी.ए. के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किया।

5.3. इस स्तर पर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा यह बताया गया है कि आरोप तय होने से पहले, संबंधित अभियुक्त व्यक्तियों ने एक के बाद एक आरोपमुक्त करने का आवेदन दायर किया, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमे की कार्यवाही में देरी हुई है। इसके बाद अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए गए और सभी छह मामलों को मिला दिया गया। संबंधित विशेष न्यायालय 02.01.2023 से 12.07.2023 तक खाली था, अब मुकदमा शुरू हो गया है और अभियोजन पक्ष ने 52 गवाहों से पूछताछ की है। इसलिए विद्वान वकील ने आग्रह किया कि एक बार मुकदमा शुरू होने के बाद, इस स्तर पर, अपीलार्थी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है।

5.4. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने, इस स्तर पर, अभिलेख से इंगित किया, अर्थात्, अपील ज्ञापन के पैराग्राफ 3 में किए गए अभिकथन, कि वर्तमान अपीलार्थी के खिलाफ पांच मामले दर्ज किए गए हैं, इस प्रकार, जब अपीलार्थी की आपराधिक

पृष्ठभूमि है, तो उसके मामले को जमानत देने के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि इस अदालत ने सह-आरोपी बजरंग शंकर, मोहम्मद नियाज़ुर रहमान उर्फ @ गुलू, मोहम्मद इरफान उर्फ मो. आलम और रिज़वाना बेघम द्वारा अपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया है। यह निर्देश पर आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आज तक, उपरोक्त अभियुक्तों ने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को उच्च मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी है।

5.5. इसलिए प्रतिवादी एन.आई.ए. के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि वर्तमान अपील को खारिज कर दिया जाए।

6. हमने पक्षकारों के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों पर विचार किया है और हमने प्रत्यर्थी एन. आई. ए. के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रदान किए गए आरोप पत्र सहित रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का भी अध्ययन किया है।

6.1. अभिलेख पर रखी गई सामग्री से यह पता चलता है कि आर. सी.-31/2018 एन. आई. ए./डी. एल. आई. बिहार के मुंगेर जिले के मुफस्सिल पुलिस थाने में 2018 की एफ. आई. आर. संख्या 323 दिनांक 07.09.2018 दर्ज करने के बाद 05.10.2018 को पंजीकृत किया गया है। जाँच एन. आई. ए. अन्वेषण ने अपने हाथ में ले ली थी। एफ. आई. आर. में 26 व्यक्तियों का नाम लिया गया है और वर्तमान अपीलार्थी को आरोपी नं. 12 के रूप में दिखाया गया है। आरोप-पत्र के कागजातों से यह पता चलेगा कि आरोपी पुरुषोत्तम लाल रजक के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाया गया है, जो वर्तमान अपीलार्थी के पिता हैं और जिनका बयान संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया है, कि वह सी. ओ. डी., जबलपुर से हथियारों की खरीद, इसकी आपूर्ति और अन्य सह-अभियुक्तों को वितरण की साजिश में शामिल रहे हैं। उक्त आरोपी द्वारा ए. के.-47 राइफलों की तस्करी अपनी पत्नी चंद्रवती देवी के माध्यम से ट्राली बैग में रखते हुए जबलपुर से जमालपुर तक 28-29 अगस्त 2018 की रात को की जा रही थी। अभियुक्त पुरुषोत्तम लाल रजक और वर्तमान अपीलकर्ता, प्रत्येक के पास चंद्रवती देवी के साथ एक ट्रॉली बैग था और उन्हें दो अन्य सह-अभियुक्तों को हथियारों की डिलीवरी के लिए जमालपुर जाने वाली कुर्ला-भागलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए कटनी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर देखा गया था। आरोप-पत्र के कागजातों से, विशेष रूप से, कंडिका 16.37 से 16.40 तक, यह पता चलता है कि जांच एजेंसी ने विभिन्न बैंकों में रखे गए अपीलार्थी के बैंक खातों के विवरण एकत्र किए हैं, जिससे यह पता चला है कि अपीलार्थी के बैंक खातों में उच्च मूल्य का लेनदेन हुआ था और यह अभियोजन पक्ष का विशिष्ट आरोप है कि अपीलार्थी को आय का

स्रोत अवैध हथियारों की तस्करी के व्यवसाय को छोड़कर है। आरोप-पत्र के पैराग्राफ 16.42 में आगे कहा गया है कि अपीलार्थी के पिता पुरुषोत्तम लाल रजक ने वर्तमान अपीलार्थी के नाम पर गाँव पडवार में पाँच एकड़ जमीन खरीदी थी। अपीलार्थी के नाम पर अन्य संपत्तियाँ भी खरीदी गईं। इसी तरह, अपीलार्थी के नाम पर वाहन भी खरीदे गए थे।

6.2. इस प्रकार, जाँच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई उपरोक्त सामग्री से, इस न्यायालय की राय है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वर्तमान अपीलार्थी के खिलाफ लगाया गया आरोप *प्रथम दृष्टया* सत्य है।

6.3. इस स्तर पर, हम यू.ए.पी.ए. की धारा 43डी (5) में निहित प्रावधानों का उल्लेख करना चाहेंगे, जो निम्नानुसार प्रदान करते हैंः-

> *"(5) तथापि संहिता में कुछ भी निहित होना, इस अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को, यदि हिरासत में है, तो जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन पर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हैः*
>
> *बशर्ते कि ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा नहीं किया जाएगा यदि न्यायालय, मामले की डायरी या संहिता की धारा 173 के तहत यह राय प्रकट करता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है। "*

6.4. उपरोक्त प्रावधानों से यह कहा जा सकता है कि यदि न्यायालय की राय है कि मामले की डायरी या संहिता की धारा 173 के तहत की गई रिपोर्ट के अवलोकन के बाद, यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाया गया आरोप *प्रथम दृष्टया* सच है, तो ऐसे व्यक्ति/आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा।

6.5. इस स्तर पर, हम इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख यानि ***राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली*** का वाद, जिसे ***(2019) 5 एस. सी. सी. 1*** में प्रतिवेदित किया गया था को भी सूचित

करना चाहेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 26,27 और 52-56 में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः-

> *"26. यह ध्यान दिया जाए कि विशेष प्रावधान, 1967 अधिनियम की धारा 43-डी, 1967 अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के चरण से लेकर उसके मुकदमे के समापन तक लागू होती है। जाहिरा तौर पर, आरोपी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर, लेकिन जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दायर करने से पहले; पहला आरोप पत्र दायर करने के बाद और पूरक या अंतिम आरोप पत्र दाखिल करने के क्रम में दं. प्र. सं. की धारा 173(8) का आगे का अन्वेषण आरोपों को तैयार करने तक या न्यायालय द्वारा आरोप तैयार करने एवं मुख्य साक्षियों द्वारा साक्ष्य को अभिलेखित करने तक हैं। हालांकि, एक बार आरोप तय होने के बाद, यह मान लेना सुरक्षित होगा कि अदालत के समक्ष सामग्री पर एक बहुत मजबूत संदेह स्थापित किया गया था, जिसने अदालत को आरोप तय करने को सही ठहराने के लिए आरोपी के खिलाफ कथित अपराध का गठन करने वाले तथ्यात्मक तत्वों के अस्तित्व के बारे में एक अनुमानित राय बनाने के लिए प्रेरित किया। उस स्थिति में, अभियुक्त को न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए एक कठिन कार्य करना पड़ सकता है कि आरोप पत्र (सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रिपोर्ट) के साथ प्रस्तुत सामग्री यह विश्वास करने के लिए उचित आधार नहीं बनाती है कि उसके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है। वर्तमान मामले की तरह संहिता की धारा 173 के तहत की गई पहली रिपोर्ट दाखिल करने के बाद जमानत के लिए किए गए अनुरोध पर विचार करते समय न्यायालय द्वारा इसी तरह की राय बनाने कीआवश्यकताहै।*
>
> *27. इसके लिए, जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई और रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की गई*

सामग्री की समग्रता और केस डायरी को शामिल करने की आवश्यकता होती है, न कि अलग-अलग साक्ष्यों या परिस्थितियों का विश्लेषण करके। किसी भी मामले में, साक्ष्य में अस्वीकार्य होने के आधार पर, इस स्तर पर दस्तावेज़ को त्यागने का प्रश्न अनुमेय नहीं है। क्योंकि, दस्तावेज़/साक्ष्य की स्वीकार्यता का मुद्दा परीक्षण का विषय होगा। न्यायालय को दस्तावेज़ की सामग्री को देखना चाहिए और इस तरह के दस्तावेज़ को ध्यान में रखना चाहिए।

52. विद्वान महान्यायवादी, खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य [खोडे डिस्टिलरीज लि. बनाम कर्नाटक राज्य, (1995) 1 एस सी सी 574, कंडिका 60] में अंतर्निहित सिद्धांत पर भरोसा करते हुए विद्वत महान्यायवादी दावा करना चाहेंगे कि अपराध के आधार पर कोई व्यवसाय नहीं हो सकता है, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 34 का कोई अनुप्रयोग नहीं होगो। वह आगे प्रस्तुत करता है कि अभियोजन पक्ष उक्त दस्तावेज़ में उल्लिखित तथ्यों का उपयोग कर सकता है और अन्य सबूतों द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ इसे साबित कर सकता है। इस तर्क को हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि, हम विद्वान महान्यायवादी के तर्क में बल पाते हैं कि जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामग्री और साक्ष्य की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता का मुद्दा मुकदमे का विषय होगा। इसके अलावा, निस्संदेह, अभियोजन पक्ष का केवल दस्तावेज़ संख्या डी-132 (ए) में गुलाम मोहम्मद भट्ट (डब्ल्यू-29) के आवास से डी-132 (ए) बरामद किया गया। खोज के दौरान अन्य स्वतंत्र साक्षियों को शामिल किया गया जो वास्वत में विचारण के दौरान साबित करना होगा। अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। अन्य स्वतंत्र साक्ष्य सहित खोज भी हैं जिसे वास्तव में मुकदमे के दौरान साबित करना होगा।

53. *अपीलार्थी ने सलीम खान [सलीम खान बनाम संजय सिंह, (2002) 9 एस. सी. सी. 670:2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1524] के विवरण पर भरोसा किया है एवं यह तर्क देने के लिये कि जिन मामलों में जहां उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण अपनाया है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, महत्वपूर्ण सामग्री/साक्ष्य को त्याग दिया गया है जो भा. द. स. कि धारा 173 अप.दं.सं के तहत रिपोर्ट में संदर्भित है और नामित अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, तो उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने के आदेश को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी का तर्क है कि उक्त निर्णय से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह सूचना देने वाले द्वारा जमानत रद्द करने के आवेदन से संबंधित है। हालाँकि, हम अपीलार्थी के तर्क में बल पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में जमानत देने के अनुरोध पर विचार करते हुए एक अनुचित दृष्टिकोण अपनाया। उच्च न्यायालय को अभिलेख पर सामग्री और साक्ष्य की समग्रता को ध्यान में रखना चाहिए था क्योंकि यह अस्वीकार्य है और इसे खारिज नहीं करना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस तय कानूनी स्थिति की अनदेखी की कि जमानत के लिए अनुरोध पर विचार करने के चरण में, सामग्री को तौलना आवश्यक नहीं है, बल्कि केवल व्यापक संभावनाओं पर उसके सामने सामग्री के आधार पर राय बनाना आवश्यक है। न्यायलय से यह आशा कि जाती है कि अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन को सुनिश्चित करें कि क्या यह प्रथम दृष्ट्या सत्य है। वास्तव में, वर्तमान मामले में, हमें जमानत रद्द करने के लिए प्रार्थना पर विचारण करने हेतु आह्वान नहीं किया गया है, बल्कि उच्च न्यायालय की शुद्धता के परीखण के वास्ते उच्च न्यायालय का रुख करने के लिए अभियुक्त को जमानत प्रदान करने हेतु, इसके बावजूद कि सामग्री एवं साक्ष्य उनके खिलाफ इंगत किए गए साक्ष्य कि*

उनके खिलाफ लगाए गए अभियोजन प्रथम दृष्टया सत्य हैं।

54. *चेन्ना बोयन्ना कृष्ण यादव [चेन्ना बोयन्ना कृष्ण यादव बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2007) 1 एस. सी. सी. 242: (2007) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 329] मामले में इस अदालत के एक फैसले में, जिसका संदर्भ दिया गया है, अदालत ने एम. सी. ओ. सी. ए. अपराधों के संबंध में जमानत देने से पहले अदालत द्वारा विचार की जाने वाली दोहरी शर्तों को दोहराया है। हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में, नामित न्यायालय ने सही राय दी है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है। चूँकि हम जमानत की प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, हमारी राय में, प्रोलिक्सिट को रोकने के लिए अन्य पहलुओं पर विस्तार करना आवश्यक नहीं है।*

55. *दुर्भाग्य से, हम प्रतिवादी को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश द्वारा प्रतिवादी को प्रदत्त जमानत को उलटना उचित समझते हैं। इसके बजाय, हम नामित न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष से सहमत है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, प्रतिवादी कथित अपराधों, विशेष रूप से 1967 के अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत आने वाले अपराधों के संबंध में जमानत देने का हकदार नहीं है।*

56. *तदनुसार, यह अपील सफल होती है। विवादित निर्णय और आदेश [जहूर अहमद शाह वटाली बनाम एन. आई. ए., 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 11185] को दरकिनार कर दिया गया है और इसके बजाय, प्रत्यर्थी द्वारा जमानत देने के आवेदन को खारिज करने वाले नामित न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई है।*

6.6. यू.ए.पी.ए. की धारा 43डी (5) में निहित उपरोक्त प्रावधानों के साथ-साथ वर्तमान मामले के तथ्यों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय और विचाराधीन घटना और आरोप पत्रों में वर्तमान अपीलार्थी की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थी के खिलाफ लगाया गया आरोप प्रथम दृष्टया सच है और इसलिए, यू.ए.पी.ए. की धारा 43डी (5) में निहित उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा।

6.7. इस स्तर पर, हम यह भी देखना चाहेंगे कि वर्तमान अपीलार्थी के खिलाफ पाँच आपराधिक पृष्ठभूमि दर्ज हैं और केवल इसलिए कि अपीलार्थी पिछले छह वर्षों से हिरासत में है, एवं वर्तमान मामले के समग्र तथ्यों एवं वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है, वर्तमान मामले में सुनवाई में इस तथ्य के कारण देरी हुई कि संबंधित आरोपी ने एक के बाद एक आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर किए। अब मुकदमा शुरू हो गया है और अभियोजन पक्ष ने लगभग 52 गवाहों से पूछताछ की है।

6.8. हमने जमानत देने के लिए वर्तमान अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार करते हुए विशेष न्यायालय द्वारा दर्ज तर्क को भी देखा है, हमारा विचार है कि विशेष न्यायालय ने उक्त आवेदन को अस्वीकार करते समय कोई त्रुटि नहीं की है।

7. वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, हम वर्तमान अपील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रुद्र प्रकाश मिश्रा, न्यायमूर्ति)

पवन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।